भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2958

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

त्रिपुरा में स्मार्ट मीटर लगाया जाना

2958. श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार द्वारा त्रिपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कितनी धनराशि अनुमोदित की गई है;

(ख) क्या भविष्य में मोबाइल फोन की तर्ज पर विद्युत सुविधा को रिचार्ज करने की सुविधा देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, मीटरों की संस्थापना के लिए 80 करोड़ रुपये के सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के साथ 319 करोड़ रुपये की परियोजना को संस्वीकृति दी गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

i. स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता मीटर: 4,47,489
ii. ग्रामीण क्षेत्रों में संचार संबंधी समस्याओं वाले प्रीपेड उपभोक्ता मीटर में: 1,00,000
iii. स्मार्ट वितरण ट्रांसफार्मर मीटर; 14,908
iv. स्मार्ट फीडर मीटर: 473

(ख) और (ग) : आरडीएसएस के तहत, मोबाइल फोन के इस्तेमाल में दी जा रही प्रीपेड रिचार्ज सुविधा की तरह ही प्री-पेमेंट मोड में उपभोक्ता मीटर लगाने की योजना बनाई गई है। मोबाइल फोन की तरह, स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को निम्नानुसार अनेक लाभ मिलते हैं जिनसे बिजली उपयोग का सुखद अनुभव होता है:

i. प्रीपेड सुविधा से उपभोक्ताओं को
    - अग्रिम रिचार्ज के माध्यम से बिजली के उपयोग के अनुसार भुगतान करने में मदद मिलती है।
    - छोटे रिचार्ज के माध्यम से उपयोग के बजट निर्धारण की छूट मिलती है।

ii. बिजली की खपत का पता लगाने में मदद मिलती है।
iii. प्रीपेड स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट मिलती है।
iv. मैनुअल मीटर रीडिंग से जुड़ी त्रुटियों को समाप्त करके मीटर रीडिंग की सटीकता बढ़ाता है।
v. स्मार्ट ऐप की विशेषताएं खपत के पैटर्न को समझने में मदद करती हैं।
vi. रूफ-टॉप सौर ऊर्जा संस्थापना के लिए नेट-मीटरिंग की सुविधा मिलती है।

****